भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

15.03.2023 के

तारांकित प्रश्न सं. 215 का उत्तर

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन

***215. डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रेलवे द्वारा उत्तराखंड में वर्ष 2014 से कितनी परियोजनाएं पूरी की गई हैं अथवा कार्यान्वित की जा रही हैं और उक्त परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति क्या है;

(ख) क्या ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उनके कल्याण के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो विकास के कौन-कौन से कार्यकलाप शुरू किए गए हैं और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के संबंध में दिनांक 15.03.2023 को लोक सभा में डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक के तारांकित प्रश्न संख्या 215 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): रेल परियोजनाएं क्षेत्रीय रेलवे-वार स्वीकृत की जाती हैं न कि राज्य-वार, क्योंकि रेल परियोजनाएं विभिन्न राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हुई हैं।

01.04.2022 की स्थिति के अनुसार, उत्तराखंड राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 18,554 करोड़ रुपये की लागत की 216 कि.मी. कुल लंबाई वाली 3 नई लाइन परियोजनाएं योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 6 किमी. लंबाई का कार्य पूरा हो गया है और मार्च, 2022 तक लगभग 5,933 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। इनमें निम्न शामिल हैः

i) **16,216.3 करोड़ रुपये की लागत वाली ऋषिकेश-कर्णप्रयाग (125 किलोमीटर) नई रेल लाइन।**

ii) **791 करोड़ रुपये की लागत वाली देवबंद-रुड़की (27 किलोमीटर) नई रेल लाइन।**

iii) **1546.24 करोड़ रुपए की लागत वाली किच्छा-खटीमा (63 किलोमीटर) नई रेल लाइन।**

उत्तराखंड़ राज्य में पूर्णत/आंशिक रूप से पड़ने वाली रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाएं भारतीय रेल के उत्तर रेलवे (उ.रे.) और पूर्वोत्तर रेलवे (पूर्वो.रे.) जोनों के अंतर्गत आती हैं।

2014 से, परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि हुई है और तदनुसार परियोजनाओं की कमीशनिंग की जा रही है। 2014-19 के दौरान उत्तराखंड राज्य में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों पर औसत वार्षिक बजट आबंटन को 2009-14 के दौरान 187 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 672 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किया गया है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन की तुलना में 259% अधिक है। इन आवंटनों को वित्त वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर 903 करोड़ रुपये कर दिया गया है (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से 383% अधिक), वित्त वर्ष 2020-21 में 1780 करोड़ रुपये (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से 852% अधिक), वित्त वर्ष 2021-22 में 4573 करोड़ रुपये (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से 2345% अधिक) और वित्त वर्ष 2022-23 में 4,948 करोड़ रुपये (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से 2546% अधिक) बढ़ा दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, इन परियोजनाओं हेतु 5,004 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक बजट आबंटन प्रस्तावित किया गया है, जो 2009-14 के दौरान औसत वार्षिक बजट आवंटन (2043 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) से 2576% अधिक है।

2014-22 के दौरान, उत्तराखंड राज्य में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से पड़ने वाले 69 कि.मी. खंड (6 कि.मी. नई लाइन, 36 कि.मी. आमान परिवर्तन और 27 कि.मी. दोहरीकरण) का कार्य 8.63 कि.मी. प्रति वर्ष की औसत दर से पूरा हो गया है।

रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, अंतिम मील संपर्कता, मिसिंग लिंक तथा वैकल्पिक मार्गों, भीड़भाड़/संतृप्त लाइनों की वृद्धि, सामाजिक-आर्थिक आधार पर शुरू किया जाता है।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई लाइन परियोजना को बजट 2010-11 में स्वीकृत किया गया था। परियोजना की प्रत्याशित लागत 16,216 करोड़ रु. है। संपूर्ण परियोजना का कार्य शुरू कर दिया गया है। अभी तक वर्तमान तिथि तक 11,237 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है। योग नगरी ऋषिकेश से वीरभद्र (5.7 किमी) खंड का कार्य मार्च, 2020 में पूरा हो गया है। किमी 6.0 से आगे, संरेखण अधिकांशतः सुरंगों में है। सभी सुरंगों और बड़े पुलों पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ख) और (ग): जी हां। कार्य निष्पादन एजेंसी रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत मधुमक्खी पालन उद्यम को बढ़ावा देने के विकासात्मक कार्य और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं मृदा एवं जल की गुणवत्ता बनाए रखने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 79.48 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।

(घ): किसी भी रेल परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण में सहयोग, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या और ये सभी कारक परियोजना की समापन लागत को प्रभावित करते हैं। उपर्युक्त बाधाओं के साथ परियोजना/(ओं) के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

******